

charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Supplies and Disposals'."

the 31st day of March, 1974, in respect of 'Secretariat of the Vice-President'."

DEMAND No. 101—LOK SABHA

"That a sum not exceeding Rs. 2,49,29,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Lok Sabha'."

DEMAND No. 102—RAJYA SABHA

"That a sum not exceeding Rs. 98,81,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Rajya Sabha'."

DEMAND No. 103—DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

"That a sum not exceeding Rs. 12,20,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Department of Parliamentary Affairs'."

DEMAND No. 104—SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

"That a sum not exceeding Rs. 3,25,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

15.35 hrs.

APPROPRIATION (NO. 2) BILL,\*  
1973

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74".

*The motion was adopted.*

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I introduce† the Bill.

I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1973-74, be taken into consideration."

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27th April, 1973.

†Introduced/Moved with the recommendation of the President.

श्री मधु लिमये (वांका) : सभापति महोदय मैंने जिन मुद्दों को पहले से लिख कर दिया है उन्हीं मुद्दों पर बोलना चाहता हूँ। सब से पहले मैं आखिरी मुद्दा लेना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, पिछली लोक सभा में मेरे मित्र स्वर्गीय नाथपाई और मैंने कई बार सदन के सामने सुझाव रखा था कि जिस तरह बमरीका में संसद की जो नियुक्तियाँ होती हैं, चाहे दूतों की नियुक्ति हो या जजों की नियुक्ति हो, उन की जांच करने का वहाँ की सीनेट को अधिकार रहता है। उसी तरह हमारी संसद की भी है। उस से एक फायदा यह होगा कि अगर कोई जजों के लिए उम्मीदवार है, या गवर्नर पद के लिये उम्मीदवार है, या दूत के लिए कोई उम्मीदवार है, उस ने अगर कोई गलत काम किया है, या कोई कुकर्म किया है तो जांच के द्वारा यह बातें साफ हो जाती और ऐसे शब्द ऊँचे पदों पर नहीं पहुँच पाते जो उन पदों के लिये योग्य नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोगों के इस देश में जो इस सदन ने और सरकार ने अभी नहीं किया।

सभापति महोदय, आप को याद होगा 1970 में हम ने एक राज्यपाल का मामला उठाया था। उन दिनों में जो बिहार के गवर्नर थे उन के बारे में कुर्सी की इजाजत से यह आरोप लगाया गया था कि उस ने बम्बई के एक बड़े स्मगलर के साथ दोस्ती कायम की थी। जब सरकार उस स्मगलर को पार-पत्र विदेश जाने के लिए नहीं दे रही थी तो वह उस समय के गुजरात के गवर्नर श्री नित्यानन्द कानूनगो के पास पहुँचे और उन की सिफारिश पर उन को पास पोर्ट मिला।

यह पत्र मैंने स्वयं सदन के सामने पेश किया था और इन्दिरा जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि वह गवर्नर को चिट्ठी लिखेंगी और उन से खुलासा माँगेंगी। बाद में उन का जवाब मेरे पास यह आया कि गवर्नर साहब यह कहते हैं, नित्यानन्द कानूनगो, कि मधु लिमये ने जो पत्र सभा के सामने रखा है . . . . .

सभापति महोदय: आप ने जो मुद्दे दिये हैं लिख कर के, हमारा ख्याल है आप ने शुरू में ही कहा है कि उन्हीं पर बोलियेगा। तो आप उन्हीं पर बोलिए।

श्री मधु लिमये: तीसरे नम्बर के मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ। मेरा मुद्दा यह था कि इन्दिरा जी को लिख कर कहा कि गवर्नर कानूनगो कहते हैं कि यह बनावटी पत्र है, उनके हस्ताक्षर सही नहीं हैं। तो मैंने उन से कहा कि यदि यह बनावटी पत्र है, उस का इस्तेमाल यदि इस तस्कर न किया है तो उस के ऊपर जाली और बनावटी पत्र के इस्तेमाल का इलजाम लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिये और यदि उस मुकदमे में साबित होता है कि वास्तव में यह पत्र जाली है, तो मेरे खिलाफ भी सदन की मान-हानि का मुकदमा चलाना चाहिए, लेकिन सत्य क्या है, उस का पता चलना चाहिए।

बहुत आग्रह करने पर सरकार के द्वारा यह जाली पत्र का केस चलाया गया। उस केस का फैसला दो महीने पहले हुआ है। मैं वह पूरा फैसला तो आप के सामने नहीं रखता हूँ, केवल उस के कुछ जुमले आप की जानकारी के लिए सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

जज साहब श्री कानूनगो के बारे में कहते हैं :

"I shall now deal with the evidence of the then Governor of Gujarat, Shri Nityanand Kanungo. I am constrained to have observe that witness, Shri Kanungo, far from telling the truth, has told innumerable lies for reasons best known to him. Except for his name, there does not appear to be a single sentence which does not contain a lie. I am constrained to make this observation because it is surprising and shocking for me to note that he who was the Union Minister for Commerce and Industry and then the Governor of Gujarat and Bihar has told countless lies intentionally to support a false case. Shri Kanungo has lied beyond redemption and there is not a single statement in the evidence which can be dealt with except for the purpose of being discarded."

यह मामला इस सदन में उठाने का कारण यह है कि मेरे मित्र यह समझें कि जब मैं कोई प्रश्न उठाता हूँ, तो बिल्कुल सच के साथ उठाता हूँ, बम्बई की अदालत ने यह साबित किया है कि मैंने जो सबत इस सदन के सामने रखे और जो अभियोग लगाये, वे बिल्कुल सही हैं। एक वाक्य भी यह पट्टा नहीं बोलता है, जिस में एक झूठ हो। आलिम्पिक गेम्स में हमारे मारे खिलाड़ी हार गये लेकिन अगर झूठ बोलने का आलिम्पिक गेम होता और श्री नित्यानन्द कानूनगो उस में हमारे प्रतिनिधि बन कर जाते, तो निश्चय ही भारत का स्वर्णारक मिल जाता। इस लिए मेरा कहना है कि इस तरह के लोग बड़े पदों पर न बैठें और राज्यागारों, जजों और दलों की नियुक्तियों में पहले उन की जांच करने, और उन में प्रश्न पूछने का अधिकार

इस सदन को या इस सदन की कमेटी को देना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा राष्ट्रीय एकात्मकता के बारे में है। मुझे पता नहीं कि ग्रह मंत्री सदन में मौजूद हैं या नहीं। मैंने पहले से नोटिस दिया था कि उन्हीं के बारे में मुझे बोलना है।

एक भारतीय सदस्य डिप्टी मिनिस्टर है।

श्री मधु लिसने. डिप्टी मिनिस्टर से मुझे क्या करना है? मैं इस वक्त उन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे वाचनालय से 10 अप्रैल की एक कतरन मिली है, जिस में कहा गया है

"Integration Council may be revived Prime Minister Indira Gandhi is understood to be considering the question of reviving the National Integration Council which has been lying dormant for over three years"

1968 में जब श्रीनगर में राष्ट्रीय एकात्मकता सम्मेलन हुआ था, तो मेरे बल ने उस का बहिष्कार किया था—और मेरी राय में ठीक ही किया, क्योंकि नकली तौर पर हम राष्ट्रीय एकात्मकता की बात करते हैं और वास्तव में हम राष्ट्रीय एकात्मकता की दिशा में नहीं बढ़ते हैं।

मैं यह सवाल इस लिए उठा रहा हूँ कि एक ओर तो प्रधान मंत्री राष्ट्रीय एकात्मकता को गिल के जीवन करना चाहती है, और यह विषय घर मंत्रालय के तहत आता है, लेकिन दूसरी ओर जब घर मंत्री हाल ही में बाका सम्बन्धी निर्वाचन-क्षेत्र में प्रचार के लिए

गये, जो उन्होंने नीतियों की चर्चा नहीं की, उन्होंने यह नहीं कहा कि मधु लिमये की नीतियाँ गलत हैं, उसके कार्यक्रम गलत हैं, या वह भ्रष्ट व्यक्ति है, बल्कि उन्होंने यह चर्चा की कि वह बम्बई है और उस को बिहार से चुनाव लड़ने का क्या अधिकार है।

श्री उमाशंकर दीक्षित भी एक जमाने में बम्बई में रह चुके हैं। आज कल तो बम्बई की फिजा भी बिगड़ गई है, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि जब वह 1930, 1932 और 1935 में बम्बई में रहा करते थे, तो किसी ने उन को नहीं कहा होगा कि ५० पी० का भैया भाया है। किसी ने कभी उनको ऐसी बात नहीं कही, बल्कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में बम्बई में कार्य करते रहे।

यह बिहार की गरिमा रही, है, जिसके लिए नेशनल डेस्टिनेशन कोमिल को बिहार की जनता का धन्यवाद देना चाहिए कि उस ने एक ऐसे व्यक्ति का जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ एक बार नहीं, तीन तीन बार जिता दिया बिहार की जनता की जो राष्ट्रपिता के प्रति भक्ति और चेतना है हम लोग का उस का गौरव करना चाहिए। लेकिन घर मंत्री जिन के नेतृत्व में नेशनल डेस्टिनेशन कोमिल का सम्मेलन होने वाला है बिहार में जाकर कहते हैं कि मधु लिमये बम्बई है उसको बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहा के नोजवाना न हा यह वह तरफ का जवाब दे दिया कि उमा शंकर जी सगा है कि डा० अम्बेदेकर, जवाहरलाल नेहरू डा० राजेन्द्र प्रसाद, ये सब लोग मूर्ख हैं और सारी अश्वत्थामान ने प्राप्त के दिमाग महो भर दी

है, क्योंकि उन लोगों ने जोच समझकर यह संविधान तैयार किया, वह कानून बनाया कि चूंकि लोकसभा समूचे राष्ट्र की पचायत है, हम लिए भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी लोक सभा का चुनाव लड़ सकता है और चूंकि राज्यविधान सभा और राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, इस लिए यदि कोई उनके लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसका उस राज्य निवासी और मतदाता होना आवश्यक है।

जिस पद को मरदार पटेल, राजगोपाला-चारी, गोविन्द वल्लभ पन्त, लाल बहादुर शास्त्री और यशवन्तराव चव्हाण ने विभूषित किया उस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया गया है, घर मंत्री बना दिया गया है, जो किसी जमाने में नेहरू परिवार के घर मंत्री रह चुके हैं। (व्यवधान) और कोई गुण मझे उन में दिखाई नहीं देता है। (व्यवधान) जो कुछ मैंने कहा, वह असमंजस नहीं है अशिश्ट नहीं है गाली नहीं है।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) उसमें कुछ मिलता-जुगता है।

श्री मधु लिमये हम का निर्णय अध्यक्ष करेंगे। अगर अध्यक्ष करेंगे कि मैंने अशिश्ट या असमंजस भाषा का प्रयोग किया है तो मैं इन गद्दों का वारिस ले लूंगा।

यह बात मध्य बात, बापू जी भी बाल दिया करने है। माननीय मंत्री पद यह रावाल अपनी पार्टी में उठाये और फिर खुद में बैठकर करें।



[ श्री मधु लिमये ]

श्री उमार्शकर दीक्षित इस वक्त सदन में मौजूद नहीं है। अगर वह यहाँ मौजूद हों, तो आज नहीं तो कल, आप उन का हाथ पकड़ कर सैंट्रल हाल के बाहर ले जाइये और सैंट्रल हाल की दीवार पर जो वाक्य मुनहरी अक्षरों में खोदे गये हैं, उन को पढ़वाइये।

क्या लिखा है

अयं निज परी वेत्ति गणना लघुचेतसाम ।

उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यानी छोटे मन वाला आदमी यह मेरा यह पराया इस तरह की बात करता है और जिस का दिल चौड़ा है जैसे बिहार की जनता का और नौजवानों का है वह लोग सोचते हैं कि—उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम्—यह समूची मानव जाति, समूची दुनिया हमारा कुटुम्ब है। इस तरह का आज दिमाग और मन बिहार की जनता रखती है। लेकिन भारत के घर मंत्री किस तरह के जीव और मनु है यह मेरी समझ में नहीं आया, किस तरह के जीव और जन्म है

एक माननीय सदस्य : 1971 में हराया इन का ।

श्री मधु लिमये घर मंत्री ने हराया ? वह तो आप डी पी खदब से पूछिये कि मैं जनता के वोट में हार गया था ठप्पा मारी से हारा ? खुद डी पी यादव कनेक्टर के सामने कहा कि मैं ठप्पा मारी से जीत गया हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कोई पेट्रीशन नहीं करता। आप पाव रुक रहिए। इस बात को काटें ? कनेक्टर के सामने उन्होंने कहा है। हमने कहा कि जब

कह ही रहे हैं तो मैं आप के खिलाफ पेट्रीशन नहीं करूंगा। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है.....

श्री शशि भूषण अध्यक्ष महोदय, गोखले और तिलक वंश की बात कर रहे थे, ब्राह्मण की बात कर रहे थे, इसलिए वहाँ से जीते..

श्री मधु लिमये नानसेन्स। मैंने जाति की बात कभी नहीं कही।

श्री शशि भूषण बिलकुल कहा।

श्री मधु लिमये मैंने कभी नहीं कहा। कमीशन बिठाइये। अगर जाति की बात मैंने कही थी यह साबित हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मैं अध्यक्ष महादय के पास इस्तीफा लिख कर देने को तैयार हूँ।

आप तैयार हैं ?

श्री शशि भूषण हा हम तैयार है।

श्री मधु लिमये ना चलिए कमीशन बिठाया जाय। मेरे मुह से (बयबयान)

सभापति महोदय यह त्रास टाक आपस में नहीं होनी चाहिए।

श्री मधु लिमये देखिये, झूठा आरोप नहीं करना चाहिए ? (बयबयान)

सभापति महोदय हाँ गया, उन को बोलने दीजिये।

श्री शशि भूषण यह जीतने की बात करते हैं। यहाँ सब जीत कर आए हैं। यह कोई नई बात करके आए हैं ?

सभापति महोदय देखिये, हल्सा मत करिए।

श्री मधु लिमये : तो अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी बिहार के ही हैं और आज के नहीं हैं, पुराने हैं, नये कांग्रेसी नहीं हैं हल्ला करने वाले आप न जाने कब से 19-20 साल से कांग्रेस आंदोलन में क्यों जेल काट चुके हैं ..

श्री शशि भूषण : और ये हत्या करने वाले लोग हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं कुछ नहीं हूँ । आप जब दूसरा काम कर रहे थे तो उस समय 17 साल की उम्र में मधु लिमये अंग्रेजों की जेल काट रहा था । आप राष्ट्रीयता मुझे मत सिखा-इये ।

श्री शशि भूषण : मैंने इन से ज्यादा जेल काटी है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीयता का पाठ मुझको न पढाइए...  
(व्यवधान)

समापति महोदय : अच्छा, हो गया, आप दोनों बड़े अच्छे आदमी हैं । उन्हें समाप्त करने दीजिये ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मुझे आगे बढ़ने दीजिये ।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य श्री मधु जी ने अभी गृह मंत्री के लिए दो तीन शब्द कहे हैं और वह यह है कि घर मंत्री किस तरह के जीव और जन्तु है यह मेरी समझ में नहीं आया, यानी गृह मंत्री किस तरह का जानवर है मोटी भाषा में..... (व्यवधान)

श्री पीन् मोबी (गोधरा) इन की हिन्दी जरा कमजोर है । इन को माफ किया जाय, इन की हिन्दी जरा कमजोर है ।

श्री बी० पी० मौर्य : नहीं, हिन्दी मैं ने पढ़ी ही नहीं ।

श्रीमन्, मेरे जैसा व्यक्ति जो हिन्दी नहीं जानता या जो हिन्दी का ठीक तरह से रूप नहीं समझता, उन्होंने किस आशय को लेकर ये दो शब्द इस्तमाल किए हैं, उम का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह जो शब्द मैं ने 'जन्तु' कहा है यह दो हजार साल पहले महाकवि कालिदास ने प्रयोग किया है और मैं जब लड़का था तो शाकुन्तल पढा करता था । वही श्लोक मैं आप को जरा सुनाता हूँ :

स्म्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशब्ध शब्दान् ;  
पयुत्सको भवति यन् सुखिनोऽपि त्रतु ;  
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोऽपूर्वं ;  
भावस्थिगणि जनान्तर सौदृशान् ॥

यह इटर की क्लाम में हमने पढा है । यह कांग्रेसियों को मालूम नहीं है । ता महाकवि कालिदास के आधार पर मैं बोलने के लिए खडा हुआ हूँ ।

अब आगे बढ़ें मैं ? आखिरी मुद्दा मेरा यह है, टोकेगे नहीं तो जल्दी खत्म हो जायगा ।

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobili): Please allow me to make a submission, Sir.

MR. CHAIRMAN: No. submission, please.

**SHRI K. NARAYANA RAO:** On a point of order. My point is this. I have been hearing the hon. Member's speech in the English translation and what exactly I heard is this: "What sort of an animal is the Home Minister?" Whatever may be the meaning in Sanskrit or Hindi, in the particular context the expression is used, it is not parliamentary. This is my submission, sir. . .

**MR. CHAIRMAN:** There is no point of order.

**SHRI K. NARAYANA RAO:** This is unparliamentary. That is my point. This particular expression, used in this particular context, is unparliamentary. This is my submission.

**MR. CHAIRMAN.** There is no point of order. Please resume your seat..

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय, अब मेरा आखिरी मुद्दा है। . . . (व्यवधान) इन को अरिस्टाटल का तर्कशास्त्र सिल्लोजिजय सिखाइएभाल मेन आर एनीमल्स। छोड़िये, न यह लाजिक जानेगे न कारिदास को जानेगे तो वहस कैसे होगी।

श्री शशि भूषण आप डाविन को जाने ताकि बन्दर की औलाद नजर आए।

श्री मधु लिमये आप शायद ग्टालिन के अष्ट अवतार को जानते है।

सभापति महोदय, अब मेरा आखिरी मुद्दा यह है कि यह सरकार समाजवाद की चर्चा करती है। तो समाजवाद मे प्लानिंग कमीशन को अपने लक्ष्यो को निर्धारित करने समय हमारे सीमित साधनो का ध्यान होना चाहिए, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में हो, देश तो पूरा एक है।

पूँजी का भंडार एक है। तो इस पूँजी के भंडार सीमित साधनों का इस्तेमाल करते समय हमारी प्राथमिकताएं कौन सी हैं, किन किन चीजों को हम वरीयता देगे इस के बारे में कोई निश्चित सिद्धान्त तय करने चाहिए। मैंने यह देखा अध्यक्ष महोदय, बिहार के भोला पास्वान शास्त्री जी बैठे हैं, जगजीवन राम जी बैठे हैं . . . . .

सभापति महोदय . बहुत टाइम लिया आप ने। अब समाप्त कीजिए।

श्री मधु लिमये एक दिन भी दे सकते है आप नियम के अनुसार। मैं तो तीन मिनट मे यह खत्म करने वाला हू।

तो बाबू जी और भोला पास्वान शास्त्री जानते है कि बिहार मे बस की छतो पर बैठ कर कितने लोग चलते है, दण्डवते जी को भी यह काम एक दफा करना पडा, और लटक कर कितने जाते है इस का पता ही नही। तो बस गाडियो के निर्माण को वरीयता देनी चाहिए या बाबा के लिए बेबी कार की ? इस का कभी फैसला होगा ? (व्यवधान) यह तो 1970 की बात है कि 'बेबी कार वाज डिलेड फार दि बाबा टू थो अप' यह हमारे मित्र ने कहा था कि पीन मोदी जी ने। (व्यवधान) . आप भी मित्र है। (व्यवधान) इसीलिए उन को अधिकार है बेबी और बाबा के बारे मे बो ने का।

तो बेबी कार बाबा के लिए— क्या इस को आप वरीयता देगे ? हो सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र मे नही है। लेकिन पूँजी का भंडार तो समूचे देश के लिए एक है।

17 करोड़ की पूंजी बटोरी गई है। हो सकता है कि वित्त मंत्री बैंको के द्वारा और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा आज नहीं कल ऋण देगे और अपने क्षेत्र में से देख रहा हूँ पुसिया बाजार बस्ती में मैंने देखा कि सिगर मेरिट सिलाई मशीन खरीदने के लिए दर्जी के बेटे को पीने छः सौ रुपये नहीं मिलते हैं। नाऊ के लड़के को हेयर कटिंग सैलून खोलने के लिए डेढ़ हजार रुपया नहीं मिलता है। छोटे किसानों को, अध्यक्ष महोदय, कुछ यादव काश्तकारों के गांवों में मैं गया, मेरे बचपन में महाराष्ट्र में और गुजरात में चमड़े की मोट से बैलों के जरिये पानी खींचा जाता था और हरयाने में ऊंट की आंखें बांध कर उसके ऊपर बन्दर को बिठा देते थे, वह मूर्ख जानवर समझता था कि कोई इंसान सवार है तो घूमता रहता था, और पशियन रहत से सिचाई होती थी। आज मशीन का जमाना है। लेकिन खेद की बात है कि महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में जो जानवरों से काम होता था बिहार में इसान अपने बून का पसीना बना कर उस काम को करवाता है, खेतों को सिंचने का, उत्तर प्रदेश में भी।

16.00 hrs.

दूसरी बात—राजधानी एक्सप्रेस चालू हो रही है जब कि तीसरे दर्जे के यात्रियों को बैठो के लिए आज जगह नहीं मिलती है। उस में काला बाजार चलता है। राजधानी एक्सप्रेस में सो कर जाने का टिकट 300 रुपये से भी अधिक है। किन वर्गों के लिए यह गाड़ियां बनाई जाती है? मैं मांग करना चाहता हूँ कि यह जो बाबा-बोबाकार

प्रोजेक्ट है या राजधानी एक्सप्रेस है, इन्हीं खर्च दिखा जाय वित्त मंत्री कहें कि अर्थ व्यवस्था को सुधारना है तो सीमित पूंजी है, सीमित पूंजी का इस्तेमाल उत्पादक कामों के लिए करना चाहिए। क्योंकि स्वयं प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि कितनी भी छोटी सी कार बनायें, कितना ही कम दाम क्यों न रखें, एक प्रतिशत से अधिक लोग जिन्दगी भर उस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह पियुपिल्ड कार जनता गाड़ी नहीं है, यह बड़े लोगों की कार है। इस लिए बस गाड़ियों का निर्माण कीजिए, तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए डिब्बे बनाइये, तभी अर्थ व्यवस्था सुधारने के कामों में कुछ मदद हो सकती है।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Scramapore): Mr. Chairman, Sir, I will raise only points.

My first point is regarding certain memorandum in respect of corruption in the Ruby General Insurance before the general insurance was taken over by the government. The employees of the Ruby General Insurance repeatedly made representations to the Finance Minister as well as to the Prime Minister. Since the year 1971 they submitted so many concrete cases, that is, the policies were issued for Fire Insurance for the godowns which were non-existent and some time after the benami claimant came that there was incident of fire and the Ruby General Insurance sanctioned money to them. Through these ways several lakhs of rupees were mis-appropriated by the management of the Ruby General Insurance which is now under Chavan's Ministry. May I ask him what steps he has taken in this matter because the staff and the officers who were in the Ruby General Insurance when it was under the Birlas they are still carrying on work in that Ruby

[Shri Dinan Bhattacharyya] General Insurance? In April 1962 a memorandum was submitted with photostat copies showing how the orders were given to the bogus claimants of the Fire Insurance policies.

Secondly, certain cases were instituted in the year 1970-71 for the evasion of wealth tax by the Birlas regarding certain shares the value of which they managed to get reduced and false statements were submitted to the government. Orders were given for the institution of a case but subsequently when the elections came, just on the eve of 1971 elections, in some papers it has come that Rs. 20 lakhs were given as a donation by the same Birla group to some Minister under whose instructions the case against the Birlas was dropped. May I know that the fate of that case is and whether even at this moment, Government are ready to reopen it so that the actual culprits may be caught?

**SHRI PILOO MODY:** Now that they have spent the Rs. 20 lakhs, they can reopen it.

**SHRI DINAN BHATTACHARYYA:** My next point is in regard to the Durgapur Steel Project. We have heard in this House many times and it has been discussed also that there is low production and continuous loss there. A memorandum has been submitted by the Durgapur Steel Employees Union in which they have made certain concrete suggestions regarding the removal of bottle-necks in the production and they have also suggested how the production can be effectively improved and how matters can be brought to a situation in which the plant may also be a profitable concern. Most probably, the hon. Minister of Steel and Mines, Shri S. Mohan Kumaramangalam has already got a copy of it, but I do not know whether he has found time to go through it or not. Since he is so much enthusiastic, if he has not got it already, I shall give him a copy.

**SHRI PILOO MODY:** He has been reading the Supreme Court judg-

ments.

**SHRI DINAN BHATTACHARYYA:** They say in their memorandum:

"The problem of the Durgapur Steel plant has started from the very beginning of the construction work when the British consortium, with the connivance of their Indian counterparts supplied outmoded, rotten and defective machinery and materials, rendering the plant incapable of achieving the initial production target of one million tonnes and thus rendered it into a sick plant."

In the concluding part, they have said:

"The accumulating loss of the Durgapur Steel Project is possible to be overcome by modification of the plant so that it can achieve 1.6 million tonnes straight production and further expenditure the production to 3.5 million tonnes that witness, Shri Kanungo, far from straight with more diversification and introduction of remunerative product-mix. Only by expansion can the fate of the Durgapur Steel Project can be saved from further erosion".

In the case of alloy steel, Government did not take any step for the expansion in the case of the Durgapur Steel Project. To those very workers whom he slanders day and night here and in West Bengal, promises were given before the election that if the Congress came to power in West Bengal, they would take "immediate steps for the expansion of the Durgapur Steel Project. But, here the workers have come forward with a concrete proposal but nothing has happened. Government say that they want the cooperation of the workers, but we find that that is only a stunt and nothing but a stunt. If they want co-operation and they want any improvements in the situations they must take the workers into confidence and act as per the suggestions of the employees.



My last point is regarding the working of the Information and Broadcasting Ministry I would like to ask whether the broadcasting centre is a broadcasting centre for the Indian people or for the ruling party.....

**SHRI PILOO MODY:** For the Congress Party.

**SHRI DINEN BHATTACHARYYA:** That is so, because the Congress Party is the ruling party here. The Information and Broadcasting Ministry is using the whole broadcasting machinery for the interests of the ruling party. Even in the report on the proceedings of the Lok Sabha, the view points of all the parties are not given. Yesterday there was the debate on the Demands of the Labour Ministry. But may I know why nothing was mentioned in the broadcast except that the CPI(M) Member Shri Dinen Bhattacharyya opened the debate? Had it been otherwise, had it been a Congress member or a ruling party Minister speaking, whatever it is, that would be given publicity. This is going on daily. You are on record that you give only four to five minutes per day for the opposition. What a wonderful democratic system. You are monopolising not only the power under one party, one leader, one government, but you are monopolising the one radio centre to propagate only for the ruling party and nobody else.

This is not the position only in regard to the proceedings of the Lok Sabha I put a question the other day to the Minister. Only the other day from April 18 to April 22, the CITU held its second Congress where three lakhs of people had gathered. But not a single word came in the radio about it. Even in Kerala, it was not broadcast though it was a such a big meeting attended by representatives from all over India and also delegates from both North and South Vietnam attending as fraternal delegates and greeting our CITU

Congress. But nothing came on the radio. This is the method, this is the way you are utilising the broadcasting medium for your own political purpose. Not only do you publish and propagate your own news, but you also suppress and distort other parties' viewpoints.

So my question is: what is the good of this radio centre, what is the good of this broadcasting medium? You talk about socialism and you talk about democracy. All this is bogus. If you are honest, you must make a statement here actually as to what is your policy regarding the broadcasting system existing under your Ministry.

**THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMAR-AMANGALAM):** So far as Durgapur is concerned, the hon. member seems to have got his facts twisted in his mind. ISCON were the consultants for the first phase, the million-tonne phase. The million tonne target was attained by Durgapur, which is admitted in one of the memoranda submitted by the very union whose spokesman he tries to be, in 1965. So the question of the machinery given in the first phase being bad or not capable of producing a million tonnes is obviously belied by this simple fact.

So far as the position after expansion was concerned, that is in 1965-66 and so on, the hon. member knows far better than I do that the unsettled conditions prevailing in Bengal from 1967 to 1970 were to a large extent responsible for the fall in production, and the party to which he belongs has no small responsibility for what happened in those years.

Recently, there has definitely been an upswing in production and though he would prefer to look upon it as a stunt, I prefer to look upon it as some measure of success of the policy

[Shri S. Mohan Kumaramangalam] of co-operation between the management and workers which is bringing results in Durgapur and which will, I am sure, bring more results. If the hon. member would choose to cut himself a little aloof from the ideological dogma which he goes on repeating day in and day out in this House, he would see the facts as they are

**SHRI DINEN BHATTACHARYYA**  
You do not have any ideological dogma?

**SHRI S. MOHAN KUMARAMANGALAM** I always listen to him. He could listen once in a while to what I say (*Interruption*)

If the hon. Member would forget those things and look at the realities of the problem I think he will be as happy as I and the workers and the management in Durgapur are that the production in the month of March was the highest since 1965. That, I think, is sufficient answer to what he said.

**SHRI DINEN BHATTACHARYYA**  
The concluding part of my question that is, regarding expansion he did not answer.

**SHRI S. MOHAN KUMARAMANGALAM** Regarding the question of the alloy steel plant the hon. Member knows that in March, 1973 record production has been done by the ASP in number of areas. So far as expansion is concerned, you know that there is a committee which is going into it, and we expect its report very soon. On the basis of its recommendations action will be taken.

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI I. K. GUJRAL)** Sir, I only regret that due to paucity of time the Demands of the Ministry of Information and Broadcasting could not be discussed,

because, had they been, it would have given me an opportunity and to my hon. friends also to talk in detail about the performance of the Ministry and of the All India Radio. It is unfortunate that sometimes, my hon. friend does make a statement which does not bear any resemblance to the realities whatsoever. I have said time and again that the policy of All India Radio is to be very objective so far as the news is concerned. That is perhaps one of the reasons why my friend hears the radio so often and he notices every slip that has taken place. I am glad, therefore, to say that he accepts the credibility which was claimed. The main point is that whenever a bulletin is broadcast it has to be kept in mind that the bulletin's length does not extend to more than 10 minutes in the morning and 15 minutes in the evening. If you think in terms of words and in terms of columns you will find that hardly about four to five columns of a newspaper can get paper covered during this limited time. The result of it is that that news naturally gets more mention which concerns the burning subjects and the news value of which is more than what my friend may attach to it.

The basic issue is that sometimes in our subjectivity and something in our own ego, he starts thinking that whenever I say or whatever he says deserves more mention because of its news value. May be, but in a vast country like India, anybody sitting at the editorial office has to see to the news value or the news worthiness of it and then decide what should be mentioned and to what extent.

Now one of the points which are made again and again here is that the opposition parties are hemmed in and they do not get any mention in the radio whatsoever. Thus, I categorically refute. From time to time, we have been carrying on surveys and been putting before the public as to how much time is given to the opposition parties as such. At this

movement, since I had no notice of what my hon. friend would say—

**SHRI PILOO MODY:** In this calculation, is the CPI considered as part of the ruling party or the Opposition?

**SHRI I. K. GUJRAL:** No; from this point of view, we put the CPI and the Swatantra parties together. *(Interruptions)*

**SHRI S. MOHAN KUMARAMAN-GALAM:** Sir, a point of order. Even though it is difficult, the hon. Member should stand when he interrupts.

**SHRI I. K. GUJRAL:** Sir, I would like to give only one instance to show how much time is given to the Opposition parties. For instance, when the election to the Lok Sabha was held, from the time when Parliament was dissolved in December, 1970 up to the end of February, 1971—I will not go into details—the Congress party, in terms of all the bulletins put together in those two months, got 17 hours 35 minutes, compared to the Opposition parties' total time which was 47 hours 21 minutes. You will recall that we allocated considerable time to the election manifestoes issued by all the political parties. The Congress Party's election manifesto got one hour and 47 minutes while the time allotted to the Opposition parties was 7 hours and 41 minutes.

**SHRI PILOO MODY:** That is because the Opposition has so much more to say.

**SHRI I. K. GUJRAL:** Whenever you have so much more to say, you got more time. You should not expect us to give you more time when you have nothing to say. That is exactly my point. Whenever you have something to say either in this House or outside, you will always get time—*(Interruptions)*. Whenever my hon. friend sits and shouts, naturally it will not get mentioned.

**THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN):** Mr. Chairman, Sir, I think I need reply to one or two points. Shri Madhu Limaye had left the House. There were certain remarks which would require no answer from us. He has recently been elected from that place and his approach is rather that of the election propaganda and election speech in the madian. So, he has tried to misinterpret the Home Minister. I do not think that a man of the status of Shri Uma Shankar Dikshit can be accused of such intentions.

Shri Bhattacharyya mentioned about the Ruby insurance. He asked a question and it was answered on 5th May, 1972. He mentioned a certain complaint made by some staff. One particular letter was brought to the notice of the Insurance Company. It was found that the man himself said that he had never written such a letter but that somebody else had made use of his name and put in that claim. If there are any specific questions like that certainly they can be gone into. If the complaints are vague, it is difficult to verify or enquire. If he has got any information, we can go into it.

**SHRI DINEN BHATTACHARYYA:** We shall.

**SHRI YESHWANTRAO CHAVAN:** Certainly. In the matter of certain tax enquiries, certain things were not allowed to be opened, because the Law Ministry's contention was that they should not be opened. But after that a specific case had been opened and the officers of the cell are enquiring into many matters. This assurance I can give to the hon. Member.

I think Shri Madhuji had mentioned in his letter that he would refer to certain questions about planning. He has not raised any.

PROF. MADHU DANDAVATE  
(Rajapur): He referred to priorities.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN:  
He himself has replied to that. Government has accepted the position that priority would be given to public transport and that certainly is the approach accepted by the Planning Commission. I think this reply is enough. He himself would have replied.

SHRI PILOO MODY. Instead of making baby cars, you should make jumbo buses.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN:  
These are suggestions in detail which could be considered. As far for the principle, I have already explained the position and I have nothing more to add.

MR CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1973-74 be taken into consideration."

*The motion was adopted*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN:  
I move:

"That the Bill be passed."

MR CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Private Members' Bills and Resolutions.

16.20 hrs.

# COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

## TWENTY-SIXTH REPORT

SHRI J. MATHA GOWDER (Nilgiris): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th April, 1973."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th April, 1973."

*The motion was adopted.*

16.21 hrs

# RESOLUTION RE ABOLITION OF RAJYA SABHA—contd.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up further discussion of the following Resolution moved by Shri Bibhut Mishra on the 30th March, 1972:—

"This House directs the Government to bring forward a Bill to amend the Constitution to provide for the abolition of Rajya Sabha".

Only 25 minutes remain.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): If my resolution is allowed to be moved, sometime may have to be given. I shall make my speech later on. I am asking for the time just to move my Resolution.